# भारत सरकार इस्पात मंत्रालय

### राज्य सभा

# अतारांकित प्रश्न संख्या 2076 07 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए

# आरआईएनएल का भूमि संबंधी स्वामित्व

### 2076. श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के प्रचालनात्मक नियंत्रणाधीन भूमि कितनी है;
- (ख) उपरोक्त भूमि का स्वामित्व किसके पास है और इस भूमि पर आरआईएनएल का नियंत्रण किस प्रकार का है;
- (ग) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य इस्पात उद्यमों के संयंत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि भी सरकार के नियंत्रणाधीन है, तत्संबंधी इकाई-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) यदि नहीं, तो आरआईएनएल की भूमि को पट्टे पर लेने के क्या कारण हैं जबकि अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भूमि का स्वामित्व उनके पास ही है;
- (ङ) क्या सरकार आरआईएनएल के परिसंपत्ति आधार को बढ़ाने और इसकी साख को बढ़ाने के लिए उसे भूमि का स्वामित्व देने पर विचार करेगी; और
- (च) यदि नहीं, तो आरआईएनएल को सीपीएसई के रूप में भूमि देने की बजाय निजी संस्था को भूमि देने का औचित्य क्या है?

#### उत्तर

## इस्पात राज्य मंत्री

# (श्री फग्गन सिंह क्लस्ते)

- (क) और (ख): राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र (वीएसपी) के प्रचालनात्मक नियंत्रण में 19,703 एकड़ भूमि है। इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के नाम से भूमि को अधिग्रहित किया गया था और इस भूमि का उपयोग करने के लिए आरआईएनएल के पास मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) है।
- (ग) और (घ): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की इकाइयों/संयंत्रों की भूमि संबंधित संयंत्रों/इकाइयों के नाम पर है। भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इस्को इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र, अलॉय इस्पात संयंत्र और विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात संयंत्र के संबंध में भूमि का स्वामित्व पूर्ण स्वामित्व आधार पर है। राउरकेला इस्पात संयंत्र के संबंध में भूमि का

स्वामित्व पट्टा पर आधारित है। आरआईएनएल की भूमि का स्वामित्व इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के पास है और आरआईएनएल के पास उसका मुख्तारनामा है।

- (ङ): सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
- (च): वर्तमान में, किसी निजी निकाय को भूमि देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में भारत सरकार की शेयरधारिता के साथ उसके सहायक/संयुक्त उद्यमों में आरआईएनएल के शेयरों के 100% विनिवेश के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया है। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के अनुरूप है।

\*\*\*